न्यायाधीश के उद्देश्यों के लिए या न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक ऐसे निर्देश देने या ऐसे आदेश पारित करने के लिए न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला माना जाएगा।यह नियम उचित आदेश पारित करने के लिए न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्ति को भी पूरा करता है जो न्यायाधीश के उद्देश्यों के लिए या न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकता है।>

9. इसलिए, हम यह ठहराने के लिए इच्छुक हैं कि उच्च न्यायालय कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ उपयुक्त मामलों में आपराधिक कार्यवाही सहित मुकदमों और कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।इस पीठ को भेजे गए कानून के प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया जाता है और मामले को अब उचित आदेशों के लिए एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

एच. एस. बी

इससे पहले जे. वी. गुप्ता, जे.

हरियाणा राज्य-अपीलार्थी।

बनाम

माधो प्रसाद,-प्रतिवादी।

सिविल माइस।सं. *1377/*सी. आई./1980।

नवंबर, 28,1980।

न्यायालय शुल्क अधिनियम *(1870* का VII)-धारा *13*-सिविल प्रक्रिया संहिता *(1908* का *V)*-धारा *151*-अपील को अक्षम के रूप में खारिज कर दिया गया-ऐसी अपील में प्रति-आपत्तियों पर भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क-क्या वापस किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय की फीस प्रेषित करने की शक्ति केवल उन शुल्कों तक सीमित है जिनका अवैध रूप से या गलत तरीके से मूल्यांकन या संग्रह किया गया है और यह उन शुल्कों तक विस्तारित नहीं है जिनका भुगतान या संग्रह न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।जहाँ एक अपील में प्रति-आपत्तियाँ दायर की जाती हैं जो स्वयं सक्षम नहीं थी और इस तरह से खारिज कर दी जाती है, उन प्रति-आपत्तियों पर लगाया गया न्यायालय शुल्क स्पष्ट रूप से एक वास्तविक गलत धारणा के तहत भुगतान किया जाता है और उसे वापस किया जा सकता है।

खंड *151* सी. पी. सी. के तहत आवेदन में अनुरोध किया गया लगाए है कि आवेदन की अनुमति दी जाए और प्रति-आपत्तियों पर गए न्यायालय शुल्क को प्रत्यर्थी-आवेदक को वापस करने का आदेश दिया जाए।

अपीलकर्ता की ओर से ए. जी. हरियाणा की ओर से अधिवक्ता एस. के. गोयल।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने कहा।

(1981)2

हरियाणा राज्य बनाम **माधो** प्रसाद (जे. वी. गुप्ता, जे)

न्याय

जे. वी. गुप्ता, जे.

1.) यह न्यायालय शुल्क की वापसी के लिए एक आवेदन है जिसे आवेदकों द्वारा प्रति-आपत्तियों पर चिपकाया गया था।इसमें यह आधार लिया गया है कि मृत प्रतिवादी के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते आवेदकों द्वारा प्रति-आपत्तियां दायर की गई थीं, लेकिन चूंकि हरियाणा राज्य की ओर से दायर की गई अपील, यानी 1979 की नियमित प्रथम अपील संख्या 1605, को अक्षम के रूप में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि मृत व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया था, इसलिए प्रति-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सका।

2. इस आवेदन की सूचना हरियाणा राज्य को दी गई थी जिसने इसका विरोध किया था।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वे क्रॉस-1 आपत्तियों पर भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी के हकदार हैं क्योंकि यह उनके द्वारा एक वास्तविक गलत धारणा के तहत भुगतान किया गया **था और** इस न्यायालय के पास ऐसी क्रॉस-आपत्तियों पर भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियां हैं।इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने आया सिंह-तिरलोक सिंह **बनाम मुंशी राम-आत्मा** राम ***(1)* पर भरोसा** रखा।दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायालय-शुल्क की वापसी के लिए न्यायालय में ऐसी कोई अंतर्निहित शक्ति निहित नहीं है और उनके तर्क के समर्थन में, जवाहर सिंह-शोभा सिंह बनाम भारत संघ और **अन्य *(2)* पर** भरोसा **किया गया है।**

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मेरी राय है कि आवेदक अपनी प्रति-आपत्तियों पर भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी के हकदार हैं।जवाहर सिंह के मामले (सुपरा) में इस अदालत की पूर्ण पीठ का निर्णय **वर्तमान मामले के** तथ्यों पर लागू नहीं होता है।इसके अलावा, इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय-शुल्क को प्रेषित करने की न्यायालय की शक्ति केवल उन शुल्कों तक सीमित है जिनका अवैध रूप से या गलती से मूल्यांकन या संग्रह किया गया है, और उन शुल्कों तक विस्तारित नहीं है जो न्यायालय-शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भुगतान या एकत्र किए गए हैं। वर्तमान मामले में, आवेदकों ने प्रति-आपत्तियां दायर कीं, लेकिन बाद में, यह पता चला कि अपील स्वयं मृत व्यक्तियों के खिलाफ दायर की गई थी और इस तरह खारिज कर दी गई थी।

(1) ए. आई. आर. 1968 दिल्ली 249.

(2) आकाशवाणी 1958 पंजाब 38.

अतः, यह एक स्पष्ट मामला है जहाँ प्रति-आपत्तियों पर न्यायालय-शुल्क का भुगतान एक वास्तविक गलत धारणा **के तहत** किया गया था।इस संबंध में, आया सिंह के मामले (उपरोक्त) **का संदर्भ** दिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है -

> "जब तक न्यायालय-शुल्क का भुगतान करने का दायित्व स्पष्ट रूप से सरल वैधानिक भाषा में समर्थित नहीं है, तब तक एक दावेदार किसी भी न्यायालय-शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।यह शायद इस आधार पर है कि

न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्ति को या तो मजबूरी में या एक **प्रामाणिक लेकिन** गलत धारणा के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशालय शुल्क की वापसी का निर्देश देने के लिए मान्यता प्राप्त है, यदि न्यायाधीश का कारण ऐसा चाहता है।यह सच है कि न्यायालय-शुल्क अधिनियम ने धनवापसी के लिए कुछ प्रावधान किए हैं और यह तर्क दिया जा सकता है कि विधायी इरादे को अन्य मामलों में धनवापसी को बाहर **करने के लिए** माना जाना चाहिए, लेकिन कई अधिकारियों ने अदालत की अंतर्निहित शक्ति को बरकरार रखा है:सी. टी. धनवापसी पूर्व ऋण न्याय।हालाँकि, यह न्यायालय शुल्क का प्रत्येक अतिरिक्त भुगतान नहीं है जिसे निश्चित रूप से वापस किया जाना चाहिए।अनिवार्य प्रावधानों के अलावा, न्यायाधीशालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग आदेश के लिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा और न्यायाधीशिक निर्धारण करना होगा कि न्यायाधीश के कारण को धनवापसी की आवश्यकता है या नहीं।जहाँ एक वकील ने गलती से सोचा कि एक रिमांड आदेश एक डिक्री के बराबर था और इस धारणा पर कि अपील को **एक डिक्री** से माना जाता है, निर्धारित राशि से बहुत अधिक अदालत-शुल्क का भुगतान किया गया था, यह धारणा एक बांड की गलती के कारण थी, और भुगतान की गई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क की वापसी का आदेश दिया गया था।हालाँकि, उनके मामले को केवल वकील की अज्ञानता के कारण अतिरिक्त भुगतान के सभी मामलों में धनवापसी के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना था, क्योंकि उच्च न्यायालय में संक्षिप्त विवरण स्वीकार करने वाले वकील का कर्तव्य था कि वह कानूनी स्थिति के बारे में पूरी तरह से सूचित हो और प्रत्येक मामले पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त मामले में, जवाहर **सिंह मामले** (उपरोक्त) पर भी विचार किया गया है और इसे अलग किया गया है।उक्त [एफ 1] फुल पीठ मामले पर विचार करते हुए, यह देखा गया है:—

"जाहिर है, पीठ गलत धारणा के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त न्यायालय शुल्क से चिंतित नहीं थी।यह था।

भगवंत सिंह **बनाम** सुरजीत कौर (एस. एस. संधवालिया, सी. जे.)

वहाँ यह मान लिया गया कि सोहन सिंह के मामले, ए. आई. आर. ***1956*** **पंजाब** 215 में पंजाब उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले ने यह विचार लिया था कि अदालत को अदालत की फीस की वापसी देने की पूरी शक्ति थी, भले ही फीस कानून के प्रावधानों के अनुसार एकत्र की गई हो और पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से इस तरह के विचार को नकार दिया।"

मामले के इस दृष्टिकोण में, धनवापसी के लिए आवेदन
न्यायालय शुल्क की अनुमति है।

5. नतीजतन, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रति-आपत्तियों पर भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क की वापसी के लिए प्रमाणपत्र कानून के अनुसार जारी किया जाए।

एनके. एस.

(1981)2

एस. एस. संधवालिया से पहले। सी. जे. और एस. पी. गोयल, जगवंत सिंह -- याचिकाकर्ता,

बनाम

सुर्जित कौर,-प्रतिवादी।

***1978* का आपराधिक संशोधन सं. *1284*।**

2 दिसंबर, 1980।

दंड प्रक्रिया संहिता *(1974* की आई. टी.*)*-खंड *125* और *127 (2)*-रखरखाव के लिए आदेश पारित-विशेष रूप से रखरखाव के मुद्दे पर सिविल कोर्ट का बाद का डिक्री-रखरखाव का आदेश-चाहे सिविल कोर्ट डिक्री के संदर्भ में परिवर्तन या रद्द करने के लिए उत्तरदायी हो-खंड *127 (2)* के प्रावधान-चाहे अनिवार्य हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां सिविल न्यायालय की डिक्री सीधे दायित्व या रखरखाव की मात्रा के मुद्दे पर है, तो यह स्पष्ट रूप से सीधे इस मुद्दे पर सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय का निर्णय है।एक बार ऐसा होने के बाद, यह नोटिस के लिए कहता है कि अधिनियम की भाषा शर्तों में अनिवार्य है।विधानमंडल ने सुनियोजित रूप से इन शब्दों का उपयोग किया है "आदेश को रद्द कर देगा या, जैसा भी मामला हो, उसी के अनुसार।" दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की खंड 127 (2) का प्रारंभिक भाग निस्संदेह एक निश्चित विसंगति निहित करता है -

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator Vijay Girdhar